विश्व कॉरपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था क्या है?

कॉरपोरेट औद्योगिक व्यवस्था पूंजीवाद की एक ऐसी अवस्था है जो विश्व स्तर पर उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग को एक ही केन्द्र से संचालित करती हैं। यानि इस अवस्था में इन चार चरणों से संबंधित पूंजी, तकनीक, कच्चा माल, श्रम से लेकर अंतिम उपभोग तक सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण एक ही कम्पनी के अधीन हो जाता है और बाजार प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है।

कॉरपोरेट का शाब्दिक अर्थ किसी बड़े संगठन या ग्रुप से संबंधित होना है। प्रतियोगी पूंजीवाद की अवस्था जो दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध से पहले थी। एक ही उत्पाद (Product) के कई उद्योग थे। उनमें स्वतंत्र बाजार प्रतियोगिता होती थी। जिस औद्योगिक ग्रुप का माल (उत्पाद) सस्ता, सुंदर और उपभोक्ता को पसंद आता, उस माल का बाजार में चलन रहता तथा इस बाजार प्रतियोगिता में वह उद्योग टिकता। बाकी उद्योग इस बाजार प्रतियोगिता से बाहर हो जाते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ग्रुपों में बंट गई एक अमेरिका के नेतृत्व में निजी पूंजीवादी धड़ा तथा दूसरा सोवियत यूनियन (यू.एस.एस.आर.) की अगुवाई में सरकारी पूंजीवादी ग्रुप जिसे समाजवादी धड़ा कहा गया। विश्व स्तर पर ये शीत युद्ध का दौर 1985 तक चला तथा अर्थव्यवस्था इन दो धड़ों में विकसित होती रही।

सन् 1991, दिसम्बर में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तथा विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से ऐसे हालत बने जहां विश्व स्तर पर औद्योगिक ग्रुप विश्वव्यापी बहुराष्ट्रीय और पार राष्ट्रीय कम्पनियां में विकसित हो गए जिसे प्राईवेटाईजेशन लिबरलाईजेशन तथा ग्लोबलाईजेशन की नीतियों से उन्हें आगे प्रोत्साहित किया गया। किसी एक माल के उत्पादन से उपभोग तक कोई अन्य कम्पनी प्रतियोगिता में नहीं रही। माना स्टील का उत्पादन करना है तो इसके कच्चे माल खनन से लेकर, इसे स्टील की शक्ल में लाना तथा उपभोक्ता के घर तक स्टील उत्पाद पहुंचाने तक की प्रक्रिया का पूर्ण नियंत्रण किसी एक कम्पनी के अधीन हो गया। ऐसे बड़े विश्वव्यापी संगठनों को कॉरपोरेट तथा इनके मालिकों को कॉरपोरेटर्स कहा जाता है। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और पार राष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में कार्यरत है। जो वाशिंगटन कनशेनसस की ग्लोबल नीतियों को राष्ट्रीय सरकारों से कदम-ब-कदम लागू करवा कर सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था कॉरपोरेटरों के पूर्ण नियंत्रण में आ चुकी है तथा अब इसको कहीं से कोई चुनौती नहीं है। सिवाय कॉरपोरेटरों के विभिन्न आपसी टकराहट एवं सर्वोच्चता के झगड़े के।

यह रुझान उत्पादन इकाइयों से सेवा क्षेत्र में आ गया जो सूचना और संचार, गूगल, ट्वीटर, वाट्सअॅप से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, बैंकिंग, बीमा, मुद्रा, शेयर बाजार आदि में ऑन लाईन व्यवस्था आदि में हम देख रहे हैं। यह क्षेत्र भी निगमीकरण (कॉरपोरेट) के अधीन आ चुका है।

आगे अब अर्थव्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि को किसानों के प्रबंधन से निकालकर विश्व आर्थिक मंच-कृषि नीति 2009 के तहत कॉरपोरेट प्रबंध के अधीन लाने की प्रक्रिया भारत सहित प्रत्येक देश में विश्वव्यापी रूप से आगे बढ़ रही है। भारत में किसान बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली, पानी पर कम्पनियों और सरकार पर निर्भर है, एक मात्र संसाधन भूमि है वह भी गिरवी पड़ी है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के भौतिक हालात भी कम्पनियों के पूर्ण नियंत्रण के बन चुके हैं।

जागरुक किसान भूमि देना नहीं चाहते अथवा अन्य कोई विकल्प के अभाव में किसान कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र का कॉरपोरेट नियंत्रण धीरे-धीरे हो रहा है।

कॉरपोरेट व्यवस्था में— माल का उत्पादन होता है जहां—

(1) प्रत्येक वस्तु माल बन जाती है—यानि वह वस्तु जिसे बाजार में खरीदा बेचा जाता है। जहां उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता के बीच दूरी बढ़ जाती है।

(2) वस्तु उत्पादन मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए करता था, जहां उत्पादनकर्ता स्वयं उपभोक्ता भी होता था। वस्तु उत्पादन की यह व्यवस्था अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की प्रधानता के काल तक (पोप, जार, सम्राट, खलीफा, राजा, महाराजा के समय तक) प्रमुखता से चलती रही।

कॉरपोरेट व्यवस्था गांव/वार्ड से लेकर विश्व स्तर तक कायम हो चुकी है। इसका असर हम देखते हैं कि पानी बिक रहा है, हवा भी बिकनी शुरू हो गई है। सेवा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भी बाजार में खरीदने-बेचने के दायरे में आ गए हैं।

बाजार का संचालन मुद्रा (डॉलर, रुपयों) द्वारा होता है। मुद्रा की भौतिक शक्ल कागज के नोट को भी ऑनलाईन करके बाजार के संचालन के इस औजार (या विनिमय के माध्यम) डॉलर-रुपयों पर भी पूर्ण नियंत्रण कॉरपोरेट जगत (या कॉरपोरेट व्यवस्था) का होता जा रहा है।

लोगों में आपसी संबंध या आचरण की तकनीक विचार है, विचारों का नियंत्रण भी संचार एवं सूचना तंत्र के सभी साधनों—ट्वीटर, चेट जी पी टी, वाट्सएप, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, ए.आई. क्लाऊड स्टोरेट, मीडिया—के जरिए पहले से ही कॉरपोरेट नियंत्रण में आ चुका है।

बच्चा क्या खायेगा, मां तय नहीं कर सकती, मां का यह परम्परागत और प्राकृतिक अधिकार अब बड़ी कॉरपोरेट कम्पनियों के हाथों में चला गया है।

बालक और टीन एजर युवा क्या गेम (खेल) खेलेगा यह माता-पिता तय नहीं कर सकते, मीडिया और कॉरपोरेट नियंत्रित संचार तंत्र तय करता है।

दुनिया के लगभग सभी देशों में विकसित माने जाने वाले यूरोप, अमेरिका सहित में राजनीति का केन्द्रीयकरण हो रहा है, सत्ता में वह पार्टी और नेता आते हैं जिनका रुझान तानाशाही और उग्र राष्ट्रवादी होता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले प्रतियोगी पूंजीवादी अवस्था में पूंजीवादी संविधानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत व्यवस्था काम करती रही।

केवल कुछ अरबपतियों (विश्व के लगभग 10 प्रतिशत लोगों) के लिए पूरी दुनिया में कुछ भी साधन और सुविधाएं उपलब्ध है। इस व्यवस्था का सांस्कृतिक सार है कि आपकी जेब में कितना धन (डॉलर, रुपया) है, उसी अनुपात में आपको साधन और सुविधाएं मिल जायेगी।

यदि डॉलर, रुपया नहीं है तो प्रकृति द्वारा फ्री में दी गई सुविधाएं—शुद्ध हवा, पीने का पानी, शौच सुविधा से भी वंचित होना पड़ सकता है।

कॉरपोरेट व्यवस्था पूंजी आधारित और बाजार निर्देशित तथा पार्टी नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो विश्व स्तर से गांव/वार्ड स्तर तक अपना नियंत्रण बना चुकी है। इसमें आम लोगों को 5 साल में वोट देने का मात्र एक मिनट का अधिकार है, जिसे भी विभिन्न रूपों और तरीकों से छिना जा रहा है।

कॉरपोरेट व्यवस्था के कारण मौसम परिवर्तन (या ग्लोबल वार्मिंग का संकट) पैदा हो गया है। जो 'जीने-मरने' या पृथ्वी पर मानव सहित सभी जीवों के अस्तित्व को ही चुनौती दे रहा है।

एक लाईन में यह कहा जा सकता है कि आज के समय की सभी बुराइयों की जड़ विश्व कॉरपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था है। आज सभी बुराइयों को प्रकृति-मानव केन्द्रित समाज व्यवस्था में शांतिपूर्ण रूपान्तरण करके मिटाया जा सकता है। इसके लिए लोगों का समर्थन प्रकृति-मानव कन्द्रित समाजशास्त्र के हक में होना अनिवार्य है तथा पर्यावरण एवं मानव विकास मॉडल अपनाना जरूरी है।

नीचे इन दो समाज व्यवस्थाओं में फर्क दिया जा रहा है–

	कॉरपोरेट सामज व्यवस्था	**प्रकृति-मानव केन्द्रित समाज व्यवस्था**
1.	यह पूंजी आधारित है।	यह प्रकृति और मानव को आधार बनाती है।
2.	यह बड़ी पार्टियों के नेतृत्व में चलती है।	यह लोगों के नेतृत्व (जनमत संग्रह) से संचालित होती है।
3.	यह हवा, पानी, भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभी को बाजार तंत्र और राजनीतिक चालबाजी के हवाले करती है।	यह सभी को शुद्ध हवा, पीने का पानी, भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सभी विकास योजनाओं से ऊपर प्रथम प्राथमिकता में लेती है और इसे अनिवार्य संवैधानिक एवं मानवीय गारंटी बनाती है।
4.	यह धनपतियों की सेवा करता है।	यह आम लोगों–वंचित, गरीब, बेसहारा लोगों को प्राथमिकता देती है।
5.	यह पूंजी की दिशा बाजार से लेती है तथा अति उपभोग एवं अल्प उपभोग का विरोधाभास पैदा करती है।	यह बाजार तंत्र को मानव समाज एवं पर्यावरण के लिए उपयोगी बनाता है तथा व्यक्तिगत आय के न्यूनतम एवं अधिकतम अनुपात 1:5 तक सीमित करके अति उपभोग एवं अल्प उपभोग को समाप्त करती है।
6.	यह महिलाओं को समान अधिकार देने की जबानी बात करती है, व्यवहार में इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझती है।	यह महिलाओं को सभी संस्थानों में 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करती है तथा सामाजिक वातावरण समता आधारित बनाती है।
7.	यह कृषि को लाभ-हानि का व्यवसाय बनाती है। और कृषि पर नियंत्रण कम्पनियों का करती है। तथा कृषि का रासायनिकरण एवं जी.एम. कृषि में रूपान्तरित करती है।	यह कृषि को प्राकृतिक (या जैविक) सजीव कृषि बनाती है। यह कृषि क्षेत्र को किसानों की लोकतांत्रिक सहकारिता के अधीन करती है।
8.	यह अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देता है तथा कृषि को तीसरे स्थान पर रखता है।	यह अर्थ व्यवस्था में कृषि को मानव जीवन का आधार समझता है तथा इसे अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान देता है। इसके लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बजट का 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में निवेश करता है।
9.	यह धन और धन स्वामियों को शक्तिशाली बनाता है।	यह लोगों का सशक्तिकरण करता है।
10.	यह समाज व्यवस्था की एक प्रक्रिया, राजनीति को प्रथम रखता है तथा संस्कृति एवं अर्थतंत्र को दूसरे दर्जे पर रखता है।	यह व्यवस्था की तीनों प्रक्रियाओं–राजनीति, संस्कृति एवं अर्थतंत्र को समान महत्व देकर गांव, ब्लाक, जिला, प्रांत से लेकर देश, पांचों स्तर पर राजनीतिक संसद के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संसदों, विधानसभाओं का गठन करती है।
11.	यह बहुराष्ट्रीय एवं पार राष्ट्रीय कम्पनियों पर प्रोमोटर शेयर के नियंत्रण का समर्थन करती है।	यह इन कम्पनियों पर 2/3 साधारण शेयरधारकों एवं 1/3 कम्पनी के सभी मजदूरों एवं कर्मचारियों

	को चुनाव के जरिए प्रबंध मण्डल में शामिल करती है। और प्रोमोटर शेयर का प्रावधान समाप्त करती है।
12. यह बाजार में हेरफेर, अनुचित वित्तीय एवं व्यापारिक गतिविधियों को शेयर बाजार के जरिए बढ़ावा देती है तथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और उसमें गड़बड़ी पैदा करती है।	12. यह शेयर-बाजार या स्टॉक एक्सचेन्ज को बंद करने का प्रस्ताव रखती है, जो बिना रोजगार पैदा किए तथा बिना निवेश के रातों-रात अरबपति पैदा करता है।
13. यह राष्ट्रों के बीच तथा राष्ट्रों के भीतर विवादों को सुलझाने में युद्ध और हिंसा को अपना अंतिम साधन समझती है।	13. यह देशों के बीच एवं प्रत्येक देश के भीतर विवादों को हल करने के लिए बातचीत, सहमति, समझौते के शांतिपूर्ण उपायों को काम में लेती है।
14. यह लोगों में फूट डालती है। सैनिक बजट में निरन्तर बढ़ोतरी करती है।	14. यह लोगों में एकता, प्रेम, सौहार्द बढ़ाती है। सभी देशों का सैनिक बजट पहले आधा करती है। बाद में सेना को पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन करने तथा आपदा प्रबंधन बल में रूपान्तरित करती है।
15. यह न्याय व्यवस्था को सत्ता, धन एवं ताकत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है।	15. यह न्याय व्यवस्था को पर्यावरणीय एवं मानवीय मूल्य पर आधारित करती है। इनकी अवहेलना करने पर अपराधी को सुधारने का उद्देश्य रखती है तथा अपराध की गंभीरता के अनुसार दण्ड देती है। मृत्युदण्ड एवं मानवीय क्रूरता को छोड़कर मानव इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दण्डों को सम्मिलित करती है।
16. यह मानव समाज का आधार पूंजी (डालर, नोट) को समझती है।	16. यह मानव समाज का आधार प्रकृति (पर्यावरण) एवं मानव को स्वीकार करती है।
17. यह मनुष्य को प्रकृति की सर्वोच्च रचना समझती है।	17. यह मनुष्य को अन्य प्रक्रियाओं की तरह प्रकृति का एक अंग समझती है, सर्वोच्च नहीं।
18. यह मनुष्य का स्वभाव (या चरित्र) निजी (स्वार्थी) या जैविक होना मानती है।	18. यह मनुष्य का स्वभाव जैव-सामाजिक मानती है। यानि इसका अस्तित्व जैविक (या निजी) है लेकिन क्रियाकलाप, रहन-सहन सामाजिक है।
19. इसका विकास मॉडल विकास, समृद्धि एवं प्रगति को मुद्रा या विकास दर में वृद्धि देखता है।	19. इसका विकास मॉडल विकास, समृद्धि एवं प्रगति को पर्यावरण के सभी संघटकों के संवर्धन एवं सुरक्षा के साथ मानवीय गुणों में चारों ओर वृद्धि में देखता है।
20. इसका विकास मॉडल मानव सहित सभी जीवों के अस्तित्व को चुनौती देता है।	20. इसका विकास मॉडल मानव सहित सभी जीवों के सहज जीवन को सुनिश्चित करता है।